लातिन अमरीका में 'वामपंथी' उभार

लातिन अमरीका के कई देशों में संयुक्त राज्य अमरीका विरोधी सरकारें चुनाव में जीत कर आयी हैं। इनमें कइयों ने अमरीका विरोधी तेवर अपनाया है। विशेष तौर पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने अपने भाषणों में अमरीकी साम्राज्यवाद के विरोध के स्वर को सर्वाधिक मुखर रूप में व्यक्त किया है। ह्यूगो चावेज की सरकार के विरुद्ध अमरीकी साम्राज्यवादी न सिर्फ जहर उगलते हैं, बल्कि इस सरकार का तख्ता पलट कराने की असफल कोशिश में भी भागीदार रहे हैं। इससे समूची दुनिया में वामपंथी कहे जाने वाले बुद्धिजीवियों से लेकर तरह-तरह के सामाजिक आंदोलनों से जुड़े लोगों के बीच ह्यूगो चावेज की सरकार के प्रति न सिर्फ सहानुभूति बढ़ी है, बल्कि कुछ तो इसके कदमों को समाजवाद की ओर एक कदम मानते हैं। खुद ह्यूगो चावेज वेनेजुएला में अपने कदमों को इक्कीसवीं सदी के समाजवाद की संज्ञा देते हैं। हमारे देश के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी खेमे में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चावेज के कदमों में आशा की किरण देखते हैं। वे उसे साम्राज्यवाद विरोधी के तौर पर चित्रित करते हैं।

बीसवीं सदी से लेकर अब तक लातिन अमरिकी देशों में निरंतर उथल-पुथल रही है। समूचे पश्चिमी गोलार्द्ध के दक्षिणी हिस्सों में अमरीकी हस्तक्षेप रहा है। इनमें सैनिक तख्तापलट होते रहे हैं। जनता के व्यापक विरोध आंदोलन रहे हैं जो कभी-कभी विस्फोटक रूप लेते रहे हैं। उन्नीसवीं सदी के शुरू से ही लातिन अमरिकी देशों में उपनिवेशवादी सत्ताओं के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुए थे लेकिन औपचारिक राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बावजूद इन देशों की राजनीतिक सत्ता में विदेशी विशेष तौर पर ब्रिटिश व संयुक्त राज्य अमरीका की दखलंदाजी रही है। बीसवीं सदी में इन देशों में अमरीकी साम्राज्यवाद निरंतर कठपुतली सत्ताएं बिठाने की कोशिश करता रहा है। इनकी अर्थव्यवस्थाएं ज्यादातर कृषि उत्पादों और खनिज सम्पदा के निर्यात पर निर्भर रही हैं। ये देश सामाजिक ध्रुवीकरण में दुनिया में सबसे तीखी मिसाल पेश करते हैं। गरीबी-अमीरी के बीच इन देशों जैसा अंतर दुनिया में कहीं नहीं है।

ऐसे में इन देशों में हाल में आये परिवर्तनों को समझने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि इनके यहां के स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद अमरीकी साम्राज्यवाद के हस्तक्षेप की चर्चा की जाय। हाल ही में सत्तासीन हुई सरकारों के वर्ग चरित्र को समझा जाय, इन सरकारों के साम्राज्यवाद के साथ सम्बन्धों की समीक्षा की जाय और इनकी समाजवाद सम्बन्धी अवधारणाओं व कदमों की पड़ताल की जाय।

I
लातिन अमरीकी देशों का स्वतंत्रता आंदोलन और अमरीकी हस्तक्षेप

मैक्सिको, मध्य अमरीकी देश कैरिबियाई टापुओं के देश तथा दक्षिण अमरीकी देश मिलकर लातिन अमरीकी देश कहे जाते हैं। पश्चिमी गोलार्द्ध के ये देश स्पेनी और पुर्तगाली उपनिवेश थे। चूंकि स्पेनी व पुर्तगाली भाषा की उत्पत्ति लैटिन भाषा से है, इसलिए इन देशों के उपनिवेशों को लातिन अमरीका कहा जाता है।

लातिन अमरीकी देशों को औपचारिक राजनीतिक आजादी आम तौर पर 1810 के दशक से लेकर 1820 के दशक तक मिल गयी थी। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि पहले ही तैयार हो चुकी थी। खासकर ब्रिटेन द्वारा स्पेन और पुर्तगाल को पराजित करने के बाद इन दोनों देशों का अपने लातिन अमरीकी उपनिवेशों से सम्पर्क बहुत कमजोर हो गया था। 1703 में मेथुएन संधि (उस समय ब्रिटेन के पुर्तगाल में राजदूत जॉन मेथुएन के नाम से इस संधि का नाम पड़ा) के जरिये ब्रिटेन ने पुर्तगाल से वाणिज्यिक विशेषाधिकार हासिल कर लिए थे। 18वीं सदी में ही ये दोनों आइबेरियाई देश (स्पेन और पुर्तगाल) वस्तुतः विश्व के पूंजीवादी विकास की दौड़ में पीछे धकेल दिए गये थे। पुर्तगाल ब्रिटेन का 'एक संरक्षित राज्य' बन चुका था। बाद में जब यूरोपीय शक्तियों के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा के कारण इन आइबेरियाई उपनिवेशवादियों के यहां राजनीतिक संकट गहराया, तब आइबेरियाई देशों से आकर बसी आबादी के वंशज पूंजीपतियों, व्यापारियों व भू-स्वामियों (क्रेयोल पूंजीपतियों) के स्वार्थ उपनिवेशवादी शासकों से टकराये और राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के लिए इन क्रेयोल पूंजीपतियों व भू-स्वामियों ने स्वतंत्रता आंदोलनों की अगुवाई की। औपनिवेशिक शासन के अंतिम दिनों तक ये क्रेयोल पूंजीपति संपदा के मुख्य स्रोतों (जमीन, खनन उद्योग, व्यापार और छोटे उद्योगों) को नियंत्रण में ला चुके थे। राज्य सत्ता उपनिवेशवादी स्पेनी राजशाही के प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रित होती थी। (लातिन अमरीका में अकेला ब्राजील ही पुर्तगालियों का उपनिवेश था।)

1810 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मुख्यत: पूंजीवादी सामाजिक उत्पति के लोग थे। अर्जेन्टाइना में बड़ी जमीनों के मालिक (हासेन्डाडोस) और धनी व्यापारी घरों से निकले नेता थे। पैराग्युए में तम्बाकू उत्पादक अगुवाई कर रहे थे। उरुग्वे में सागर तट के पशुपालक तथा अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाले व्यापारी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे थे। वेनेजुएला में शक्तिशाली भूस्वामियों के बेटे मिराण्डा और सीमोन बोलीवार स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। चिली में भू-स्वामी, खदानों के मालिक और धनी व्यापारी **1810** के आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। यहां **1810-11** के काल का सबसे महत्वपूर्ण नेता उपनिवेश का सबसे धनी व्यक्ति– व्यापारी, भूस्वामी और वकील– जुआन मार्तिनेज डे रोजास था।

स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई करने वाले इन वर्गों के स्वार्थ लातिन अमरीकी देशों के भावी विकास की दिशा तय कर रहे थे। एक लेखक के शब्दों में;

> "अठारहवीं सदी के उदारवादी दर्शन, जिसने यूरोप में पूंजीवादी जनवादी क्रांतियों को जन्म दिया था, का उपयोग लातिन अमरीका में इस क्रांति के सिर्फ एक हिस्से को पूरा करने के लिए यानी राजनीतिक आजादी हासिल करने के लिए किया गया। यूरोपीय पूंजीपति वर्ग द्वारा सामंतवाद के विरुद्ध दिये गये तर्कों का इस्तेमाल क्रेयोलों द्वारा स्पेनी राजशाही के विरुद्ध किया गया था। यूरोप में उदारवाद औद्योगिक पूंजीपति वर्ग का सिद्धान्त था, जबकि लातिन अमरीका में यह भूस्वामियों, खदान मालिकों और व्यापारियों की विचारधारा थी। जहां यूरोप में उदारवाद भूस्वामियों के विरुद्ध औद्योगिक पूंजीपति वर्ग के औजार के बतौर सेवा करता था, वहां यह लातिन अमरीका में स्पेनी एकाधिकार के विरुद्ध भू-स्वामियों और खदान मालिकों द्वारा इस्तेमाल हुआ। वहां पर इसने औद्योगिक संरक्षणवाद के मकसद की सेवा की, यहां पर इसने मुक्त व्यापार की सेवा की।"
>
> **(Luis Vitale, Historia de Chile, quoted by Ardre gunder Frank in" Lumpen Bourgeoisie and lumpen Development", Page-46, Cornerstone Publication, Kharagpur, India, 2004, अनुवाद हमारा)**

लातिन अमरीकी देशों के नए शासक वर्गों ने उन्नीसवीं सदी में विकास की जो दिशा अपनायी उसने इन देशों को यूरापीय मंडी के मूलत: कच्चे माल के निर्यातक देशों में तब्दील कर दिया। इसने यूरोपीय औद्योगिक मालों के लिए बाजार मुहैया कराया। उन्नीसवीं सदी तक संयुक्त राज्य अमरीका की भी निगाह लातिन अमरीकी देशों पर पड़ चुकी थी।

1823 में संयुक्त राज्य अमेरीका के विदेश सचिव जेम्स मुनरो ने मुनरो सिद्धान्त **(Moneroe Doctrine)** पेश किया जिसके अनुसार, पश्चिमी गोलार्द्ध के इन देशों को संयुक्त राज्य अमरीका के प्रभाव क्षेत्र के बतौर घोषित किया गया और यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा इस क्षेत्र में घुसपैठ करने की कार्यवाही को संयुक्त राज्य अमरीका विरोधी कार्यवाही कहा गया। बाद में बीसवीं सदी की शुरुआत में अमरीकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने लातिन अमरीकी देशों में अपने सैनिक हस्तक्षेप के अधिकार की घोषणा की। इसे मुनरो सिद्धान्त का रूजवेल्ट उप सिद्धान्त **(Corollary)** बताया गया। बीसवीं सदी से अब तक यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमरीका का प्रभाव क्षेत्र रहा है। इसे अमरीकी साम्राज्यवादियों की पश्चभूमि **(Backyard)** कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमरीका समूचे लातिन अमरीका में सैनिक तख्तापलट सहित तरह-तरह के खुले और गुप्त अभियान चलाकर अपनी पसंद की सत्ताएं स्थापित करता रहा है। इस तरह के अभियान **1954** में ग्वाटेमाला में, **1983-84** में ग्रेनाडा में, **1981-82** में अल-सल्वाडोर में, **1981-90** के दौरान निकारागुआ में, **1989-90** में पनामा में और **1994-2000** में हैती में चले हैं जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अमरीकी साम्राज्यवाद की सैनिक दखलंदाजी रही है।

अमरीकी साम्राज्यवादी लातिन अमरीकी देशों में जितनी ही अधिक दखलंदाजी करते रहे हैं, उतना ही उनके विरुद्ध इन देशों में जनाक्रोश बढ़ता रहा है। **1930** के दशक से लेकर **1970** के दशक तक अमरीकी साम्राज्यवादियों को लातिन अमरीकी देशों के शासक वर्गों के एक हद तक के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। **1930** के दशक और **1940** के दशक में मैक्सिको ने विदेशी पेट्रोलियम कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया था। इन कम्पनियों में ब्रिटिश और अमरीकी पूंजी लगी हुई थी। इसी प्रकार, ब्राजील, अर्जेन्टाइना और चिली द्वारा व्यापार के संरक्षणात्मक अवरोधों द्वारा राष्ट्रीय उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। इससे समूचे लातिन अमरीकी इलाके में रणनीतिक उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का एक सिलसिला चल पड़ा था। **1950** के दशक में ग्वाटेमाला की सरकार ने एक अमरीकी कम्पनी यूनाइटेड फ्रूट कम्पनी के मालिकाने की जमीन को जब्त करके किसानों के बीच बांट दिया था। इसका जवाब अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा वहां के राष्ट्रपति आरबेन्ज के विरुद्ध तख्तापलट कराकर दिया गया। कई लातिन अमरीकी देशों में, **1960** और **1970** के दशक के दौरान ऐसी सरकारें अस्तित्व में आयीं जिन्होंने कुछ सुधारवादी कदम उठाये। इन सत्ताओं ने ट्रेड यूनियनों को कानूनी मान्यता दी तथा कुछ सामाजिक सुविधायें उपलब्ध करायीं। औद्योगिक मजदूर वर्ग और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के एक हिस्से के लिए सार्वजनिक शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायीं। रणनीतिक उद्योगों का

राष्ट्रीयकरण करने में इन सरकारों ने साम्राज्यवादी कम्पनियों को मुआवजा भी दिया। इसके साथ ही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अपने देशों में शाखाएं खोलने का मौका देने के साथ ही कई कम्पनियों को नये क्षेत्रों में निवेश करने का रास्ता दिया गया। उन्हें प्रत्यक्ष निवेश और मुनाफे को बाहर ले जाने की छूट दी गयी। लातिन अमरीकी हुकूमतों ने निवेश हुई विदेशी पूंजी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारी मुनाफा बटोरने में भी मदद पहुंचाई। 1960 और 1970 के दशक में कई लातिन अमरीकी सरकारों द्वारा कुछ रेडिकल कदम उठाने की ओर जाने का एक कारण क्यूबा की क्रांति भी थी।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों में आये ज्वार के कारण और समाजवादी खेमे की मौजूदगी तथा क्यूबा की क्रांति के बाद जब कुछ सरकारें रेडिकल सुधार के कदम अपने एजेन्डे में ला रही थीं, उसी समय लातिन अमरीकी देशों के पूंजीपति वर्ग और बड़ी जमीनों के मालिकों तथा धनिक तंत्र के एक हिस्से ने इन सत्ताओं को उखाड़ फेंकने के लिए सेना, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अमरीकी साम्राज्यवादियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। अमरीकी साम्राज्यवादियों ने इन लातिन अमरीकी देशों की सेना की सांठगांठ से चिली, अर्जेन्टाइना, ब्राजील और उरुग्वे की सरकारों का तख्तापलट करा दिया। नये सैनिक तानाशाहों को सत्ता में बैठा दिया गया। इसके बाद, लातिन अमरीकी हुकूमतों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का गठजोड़ मजबूत होता गया। औद्योगिक व बैंक क्षेत्र का निजीकरण शुरू हो गया। 1980 के दशक से निजीकरण, उदारीकरण और 'मुक्त बाजार' की नीतियां तेजी के साथ लागू होना शुरू हो गयीं। अमरीकी साम्राज्यवाद का शिकंजा इन देशों में पुनः कसता गया।

II
1980 के दशक से जारी निजीकरण की प्रक्रिया और कर्ज का संकट

1960 और 1970 के दशक में लातिन अमरीकी देशों के कुछ रेडिकल सुधारों का मतलब यह नहीं था कि वहां मजदूरों और किसानों की जिंदगी में बेहतरी या कोई बुनियादी परिवर्तन आ गया था। उस दौर में भी मजदूरों का भयानक शोषण होता था और खेत मजदूरों व किसानों की रक्षा के लिए कोई सामाजिक कानून नहीं थे। लातिन अमरीकी देश मुख्यतया प्राथमिक मालों के निर्यातक थे। फिर भी बाद के दशकों की तुलना में स्थिति कम बुरी थी।

पिछली शताब्दी के अंतिम 25 वर्षों में लातिन अमरीकी देशों के पूंजीपतियों के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अमरीकी साम्राज्यवाद की इस क्षेत्र में प्रभुत्वकारी स्थिति से भारी मुनाफा बटोरा है। वैश्वीकरण के नाम से जानी जाने वाली इस नयी विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के मुख्य आधार हैं : विदेशी कर्जों पर लम्बी अवधि में ब्याज भुगतान; प्रत्यक्ष तथा पोर्टफोलियो निवेश से होने वाले मुनाफों का व्यापक पैमाने पर साम्राज्यवादी देशों में स्थानांतरण; मुनाफे में चलने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की खरीद व अधिग्रहण के साथ-साथ वित्तीय कठिनाई झेल रहे राष्ट्रीय उद्यमों की खरीद तथा कठिन मेहनत वाले स्वीट शॉप्स, ऊर्जा स्रोतों और कम मजदूरी वाले मैन्युफैक्चरिंग तथा सेवा क्षेत्र के उद्योगों की खरीद व अधिग्रहण; तरह-तरह की उत्पादों, पेटेन्टों और सांस्कृतिक मालों पर रॉयल्टी भुगतान से किराये की वसूली; और परम्परागत बाजार की अच्छी जानकारी तथा ऐतिहासिक जुड़ाव के जरिये लातिन अमरीकी देशों में अमरीकी निगमों और बैंकों का प्रभुत्व।

1982 तक लातिन अमरीकी देशों में 257 अरब डॉलर तक का कर्ज सरकारों और निजी क्षेत्र को अमरीकी बैंकों ने दे रखा था। यह समूची तीसरी दुनिया के संचित कर्जों के 50 प्रतिशत से ज्यादा था। 1982 में "कर्ज संकट" की शुरुआत के साथ ही इन देशों में बैंक के कर्जों में भारी पैमाने पर कमी कर दी गयी थी। फिर भी एक दशक में इस क्षेत्र में संचित विदेशी कर्ज 257 अरब डॉलर से बढ़कर 452 अरब डॉलर पहुंच गया। यह उस समय हुआ जबकि इस दौरान 170 अरब डॉलर का ब्याज भुगतान कर दिया गया था।

1990 के दशक तक पूंजी के प्रवाह के संघटन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गये थे। अब कर्ज का स्थान शेयरों में निवेश ने ले लिया। लेकिन इसके बावजूद अधिकांश लातिन अमरीकी देशों में कर्ज का भुगतान उनके निर्यात की आय का 50 प्रतिशत के स्तर पर था। इस स्तर को विश्व बैंक "नाजुक" के तौर पर परिभाषित करता है। 1998 तक यह कर्ज 698 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था जो "कर्ज संकट" के सबसे कठिन साल 1987 से 64 प्रतिशत अधिक था। इस कर्ज से सिर्फ 1995 में अमरीकी बैंकों नें 67.5 अरब डॉलर की आमदनी बटोरी।

इसी प्रकार शेयर बाजार में विदेशी निवेश अधिकांश लातिन अमरीकी देशों में बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अधिकांशतः ब्राजील और मैक्सिको में केन्द्रित है। 1980 के दशक में कर्ज संकट के ठीक पहले के

वर्षों में पोर्टफोलियो निवेश लातिन अमरीकी देशों से बाहर जा रहा था लेकिन 1992 के बाद लातिन अमरीकी देशों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में ज्यादा बढ़ा है।

पूरे 80 के दशक में वैश्विक पूंजी शेयर पूंजी के रूप में साम्राज्यवादी देशों की तरफ जाती थी जबकि साम्राज्यवादी बैंकों के कर्जे पिछड़े हुए देशों की तरफ निर्देशित थे। लेकिन 90 के दशक में स्थिति में भारी बदलाव आ गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की मात्रा बढ़ गयी और यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यदि समूची दुनिया में 223 प्रतिशत बढ़ा तो लातिन अमरीकी देशों में यह 600 प्रतिशत बढ़ा। लातिन अमरीकी देशों में कुल निवेश का लगभग 62 प्रतिशत ब्राजील, मैक्सिको और अर्जेन्टाइना में था, जबकि चिली, कोलम्बिया, पेरू और वेनेजुएला का मिलाकर 26 प्रतिशत था।

अधिकांश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सार्वजनिक उद्यमों के निजीकृत होने पर खरीदने में लगाया गया। इसमें से नाममात्र का ही किसी नयी पूंजी के निर्माण की प्रक्रिया में लगा। इस समूचे क्षेत्र में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 68 से लेकर 75 प्रतिशत तक स्थानीय कम्पनियों के अधिग्रहण में लगा था। इससे अधिकांश बड़ी कम्पनियां अमरीकी बहुराष्ट्रीय निगमों के हाथों में आ गयीं। 1999 तक 100 सबसे बड़े लातिन अमरीकी निगमों में से 33 विदेशी निवेशकों, इनमें भी अधिकांशतः अमरीकी निवेशकों के हाथों में आ चुके थे।

इसी प्रकार रॉयल्टी और लाइसेन्स की फीस साम्राज्यवादियों के पास भारी मात्रा में गयी। यह जहां 1996 में 14% थी वहीं 1997 में बढ़कर 20% तक हो गयी।

लातिन अमरीकी देशों के वित्तीय तंत्र में विदेशी पूंजी की गिरफ्त लगातार बढ़ी है। 1990 से लेकर 2002 तक अर्जेन्टाइना के बैंकों की परिसम्पत्ति में विदेशी हिस्सा 10% से बढ़कर 48% हो गया। इसी समयावधि के दौरान ब्राजील के बैंकों में विदेशी हिस्सा 6% से बढ़कर 27%, चिली में 19% से बढ़कर 42%, मैक्सिको में 2% से बढ़कर 82% , पेरू में 4% से बढ़कर 46% तथा वेनेजुएला में 1% से बढ़कर 34% हो गया। बैंकों की परिसम्पत्तियों में विदेशी मालिकाने की यह बढ़ोत्तरी इन देशों की साम्राज्यवादी वित्तीय तंत्र पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाती है।

जहां अमरीकी साम्राज्यवादियों का लातिन अमरीकी देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वे लातिन अमरीकी देशों से भारी मुनाफा बटोरते हैं, वहीं व्यापार भी अमरीकी साम्राज्यवादियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अमरीकी निर्यात का करीब 25 प्रतिशत लातिन अमरीका को जाता है। दुनिया का यह एकमात्र क्षेत्र है जो अमरीकी साम्राज्यवादियों को चालू खाता अधिशेष उपलब्ध करता है। इस प्रकार, लातिन अमरीका, अमरीकी साम्राज्यवादियों के लिए इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि यह दुनिया भर के अन्य क्षेत्रों में हो रहे व्यापार घाटे की भरपायी करता है और अमरीकी साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण मुनाफे का स्रोत है।

1980 से 1999 के बीच लातिन अमरीका ने ठहराव और बीच-बीच में संकट झेला है। इन देशों में 1980 के दशक को "खोया हुआ दशक" (The lost Decade) कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने कर्ज भुगतान के जरिये यहां से बड़े पैमाने पर मुद्रा स्थानांतरण करके यहां की अर्थव्यवस्था को खंगाल डाला है। नये कर्जों और पुराने कर्जों की उगाही में फिर से समझौतों के साथ जुड़ी शर्तों के कारण उत्पादन व्यवस्था कमजोर हो गयी और रोजगार में कटौती की गयी। पूंजी की नयी आगत की तुलना में ज्यादा पूंजी बाहर जाती रही। इससे अर्थव्यवस्थाएं और ज्यादा ठहराव का शिकार होती गयीं।

1980 के दशक से मजदूर वर्ग और अन्य मेहनतकशों पर और बोझ बढ़े। उनकी मजदूरी में कटौती की गयी। 1970 के दशक तक मजदूरों को सैनिकों के हमलों का सामना करना पड़ता था। 1980 के दशक में आर्थिक नीतियों के कारण पूंजी और श्रम के रिश्तों में बदलाव आने से ये हमले और तेज हुए। 1990 के दशक में इन्हीं आर्थिक नीतियों के हमले के अंतर्गत अब पूंजी के पक्ष से श्रम पर और ज्यादा बड़ा हमला विश्व बैंक ने श्रम बाजार में सुधार के बड़े अभियान के तहत बोल दिया।

इससे लातिन अमरीकी देशों में आय के वितरण और उत्पादन के संसाधनों की पहुंच में असमानता और भी तेजी से बढ़ी है। एक तरफ पूंजीपति हैं, जिनके मुनाफे दिन दूने रात चौगुने बढ़े हैं। उनकी अघोषित आय बहुत ज्यादा है। उनके इस मुनाफे में हिस्सेदार शासक वर्ग के राजनीतिज्ञ, बैंकर और इसी तरह के अन्य लोग हैं। दूसरी तरफ, व्यापक गरीब आबादी है जिनकी आय सही मायने में बिल्कुल नहीं बढ़ी है। इस गरीबी में निम्न पूंजीपति वर्ग के कुछ हिस्से चले गये हैं। इस बढ़ती हुई गरीबी को बड़े पैमाने पर शहरों में देखा जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में पहले से ही व्यापक गरीबी रही है। लेकिन 1980 के दशक से सबसे अधिक गरीबी शहरों में केन्द्रित हो गयी है। नये शहरी गरीब महज गावों से आये गरीब नहीं हैं बल्कि भारी तादाद में वे मजदूर हैं जिन्हें काम से निकाल दिया गया है और वे अब अनौपचारिक क्षेत्र

में काम करने के लिए अभिशप्त हैं। लातिन अमरीकी देशों में गरीबों की बढ़ती फौज दूसरी या तीसरी पीढ़ी के मजदूरों से बनी है जो अधिकाधिक झुग्गी-झोंपड़ियों वाली बस्तियों में जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं।

आय के वितरण की असमानता के मामले में लातिन अमरीकी देश दुनिया में सबसे आगे हैं। व्यापक गरीबी और रोजगार के अवसरों की निरंतर होती कमी ने व्यापक जन-असंतोष को जन्म दिया है। जन-असंतोष को अभिव्यक्ति देने वाले तरह-तरह के संगठन बने हैं। जन-संघर्षों की रफ्तार में तेजी आयी है। ऐसे हालात में जन-असंतोष पर सवारी करके ऐसी सरकारें अस्तित्व में आयी हैं जो 1960-70 के दशक के कल्याणकारी राज्य व राष्ट्रवादी स्वर लिए हुए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा थोपी गयी नीतियों का विरोध करते हैं और अमरीकी साम्राज्यवाद की लातिन अमरीका में प्रभुत्वशाली स्थिति के विरोध में स्वर उठाते हैं। अमरीकी साम्राज्यवाद की पश्चभूमि में उसके वर्चस्व के कमजोर होने की परिस्थितियां निर्मित होती जा रही हैं।

III
अंतर-साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा और लातिन अमरीका में इसका प्रभाव

अभी तक अमरीकी साम्राज्यवाद की पश्चभूमि रहे लातिन अमरीका में उसके प्रभाव को चुनौती अन्य साम्राज्यवादियों से विशेषकर यूरोपीय यूनियन से मिल रही है। अमरीकी साम्राज्यवाद की आर्थिक ताकत को दुनिया के अन्य हिस्सों में भी यूरोपीय यूनियन से चुनौती मिलनी शुरू हो गयी है। इस समय लातिन अमरीका से व्यापार के मामले में अमरीका पहले नम्बर पर इसलिए है क्योंकि मैक्सिको के साथ नाफ्टा (NAFTA) के कारण उसके घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। अमरीका द्वारा लातिन अमरीकी देशों में कुल निर्यात का दो-तिहाई अकेले मैक्सिको को जाता है।

> "2000 में लातिन अमरीका में 25 सबसे बड़ी विदेशी कम्पनियों में 14 कम्पनियां यूरोपीय थीं, जबकि 11 कम्पनियां अमरीकी थीं। यूरोप से आने वाला निवेश भी उत्तर से आने वाले (El Norte-North- यानी अमरीका से) निवेश को पीछे छोड़ना शुरू कर चुका है।" (Latin America tops Asia in luring Foreign investors, Wall St. Journal, Feb22, 2002, quoted in Analytical Monthly Review, Dec. 2003, Page-10, अनुवाद हमारा)

अमरीकी साम्राज्यवादियों की आर्थिक हैसियत में इस गिरावट का प्रभाव लातिन अमरीकी देशों में स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ता है। यूरोपीय यूनियन से चुनौती मिलने के साथ ही लातिन अमरीका में संयुक्त राज्य अमरीका को चीन से भी चुनौती मिलनी शुरू हो गयी है। चीन ने पिछले दो वर्षों में इस क्षेत्र के कई देशों के साथ व्यापार और सैन्य करार किए हैं। इन देशों में, पिछले 6 वर्षों के दौरान चीन से आयात 6 गुना बढ़ गया है। दुर्लभ रणनीतिक संसाधनों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए चीन अगले दशक तक सड़कें, बंदरगाह और अन्य ताने-बाने का निर्माण कर रहा है। चीन वेनेजुएला में कई बड़ी परियोजनाओं को लागू कर रहा है। वेनेजुएला के तेल, बोलीविया की प्राकृतिक गैस और महत्वपूर्ण खनिजों तक अपनी पहुंच कायम करना इनमें शामिल है।

अपने प्रभाव क्षेत्र में चीनी खतरे को भांप कर अमरीकी कांग्रेस दो सुनवाइयां भी कर चुकी है। पिछले वर्ष कांग्रेस के समक्ष बोलते हुए उस समय पश्चिमी गोलार्द्ध मामले के सहायक विदेश सचिव रोजर नोरियेगा ने यह घोषणा की कि,

> "प्रशासन आर्थिक समझौतों में ऐसे किसी भी संकेत पर ध्यान देगा जो इस क्षेत्र में हमारे मुख्य उद्देश्यों के विपरीत काम करने वाले राजनीतिक सम्बन्धों को जन्म देते हों।"

लातिन अमरीकी देशों में पिछले दो दशक से लागू की गयी आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप पैदा हुए आर्थिक व राजनीतिक संकट और तद्जन्य जन असंतोष ने वहां ऐसी सरकारों के आने में मदद पहुंचायी है जो अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक द्वारा निर्देशित नीतियों के विनाशकारी परिणामों के विरुद्ध आवाज उठा रही हैं। समाजवाद को विकल्प के तौर पर बताने वाली ये सरकारें अमरीकी विदेश नीति की किसी गलती या इस या उस नेता के गलत निर्णयों के कारण नहीं चुनी गयीं। ये अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित नीतियों के लातिन अमरीका में विनाशकारी प्रभावों के कारण अस्तित्व में आयी हैं।

आर्थिक तौर पर पीछे जाने के बावजूद अमरीकी साम्राज्यवाद सैनिक तौर पर सर्वाधिक शक्तिशाली है। दुनिया के तमाम क्षेत्रों में इसके नौ-सैनिक बेड़े और और फौजी अड्डे हैं। यह अपनी आर्थिक हैसियत में गिरावट को रोकने के लिए फौजी तौर-तरीकों पर अमल करता रहा है। लातिन अमरीका में यह आये दिन फौजी तरीकों के जरिये प्रभुत्व बनाये रखने का प्रयास करता रहता है। लातिन अमरीका में यह 'प्लान कोलंबिया' के नाम से अरबों डॉलर खर्च करके वहां के

एफ.ए.आर.सी. एवं अन्य छापामार संगठनों के विरुद्ध सैन्य अभियान चला रहा है हालांकि इसके लिए वह नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने का बहाना बना रहा है। 'प्लान कोलंबिया' के तहत इसने न सिर्फ कोलंबिया में बल्कि बोलीविया, पेरू और मैक्सिको तक में सरकारों को बाध्य किया है कि वे अपने-अपने यहां कोका की खेती को जलायें। इसके अतिरिक्त, अमरीकी साम्राज्यवादी लातिन अमरीकी देशों में 'जनतंत्र के लिए राष्ट्रीय निधि' (National Endowment for Democracy) नाम की संस्था के जरिये वहां की अमरीका विरोधी सरकारों के विरुद्ध प्रचार करने में लाखों करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं और अपनी पिछलग्गू सरकार चुनने में इस निधि का इस्तेमाल करते हैं।

इसके अतिरिक्त वे सी.आइ.ए. के जरिए राजनीतिक हत्याओं का सिलसिला जारी रखने और सीधे फौजी हमले करके अलग-अलग देशों में अपनी पिट्ठू सरकारें कायम करने की कोशिश करते रहे हैं। इसके बावजूद, ठीक अपनी नाक के नीचे क्यूबा में वे तमाम आर्थिक, राजनीतिक व सैनिक दबावों को आजमा लेने और एजेण्टों के जरिये फिदेल कास्त्रो की हत्या कराने की कोशिशों के बावजूद अभी तक उनकी सरकार को नहीं उलट सके।

लातिन अमरीका में अब अकेले क्यूबा नहीं है। कई अलग-अलग तरह से अमरीकी प्रभुत्व का विरोध करने वाली सरकारें अस्तित्व में आ गयी हैं। अमरीकी साम्राज्यवादी इनको अपदस्थ करना चाहते हैं। लेकिन सैनिक घुसपैठ के परिणाम अमरीकी साम्राज्यवादी समझते हैं। वे अभी राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धौंसपट्टी का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने स्पेनी हवाई जहाज निर्माता को निर्यात लाइसेन्स देने से इसलिए इंकार कर दिया क्योंकि वह अमरीकी प्रौद्योगिकी से बना हवाई जहाज वेनेजुएला को बेच रहा था। स्पेन की सरकार ने अमरीकी धौंसपट्टी को किनारे करते हुए वैकल्पिक यूरोपीय प्रौद्योगिकी से बना हवाई जहाज वेनेजुएला को बेचने का फैसला लिया है। अमरीका, लातिन अमरीकी देशों को हर वर्ष 3.5 अरब डॉलर के हथियार बेचता रहा है। हाल ही में ब्राजील, अर्जेन्टाइना और वेनेजुएला ने मिलकर एक हथियार उद्योग खोलने का फैसला किया है। यह अमरीकी साम्राज्यवादियों के न सिर्फ मुनाफों के लिए एक भारी झटका है बल्कि यह उसके प्रभुत्वकारी मंसूबों पर भी एक चोट है

IV
लातिन अमरीकी देशों में आये परिवर्तन

लातिन अमरीकी देश 2.5 करोड़ वर्ग कि.मी. से ज्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन सबकी आबादी 54 करोड़ से ऊपर है। इन देशों में मैक्सिको, अर्जेन्टाइना और ब्राजील सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थायें हैं। इन देशों का औद्योगिक आधार अन्य लातिन अमरीकी देशों की तुलना में बहुत बड़ा है। भौगोलिक तौर पर मैक्सिको उत्तरी अमरीका में आता है और नाफ्टा के जरिये संयुक्त राज्य अमरीका के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। ब्राजील और अर्जेन्टाइना दक्षिण अमरीका में आते हैं। मध्य अमरीका के देशों पर, क्यूबा को छोड़कर कैरिबियाई द्वीप समूह के देशों और दक्षिण अमरीकी देश कोलम्बिया पर अमरीकी साम्राज्यवादियों का शिकंजा ज्यादा कसा हुआ है।

बीसवीं शताब्दी में लातिन अमरीकी देशों की सामाजिक संरचना में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। जहां पहले ये गांव आधारित कृषि अर्थव्यवस्था पर टिके समाज थे वहां आज ये शहर केन्द्रित औद्योगिक समाज में बदल गये हैं। उन्नीसवीं सदी में जहां फार्मरों-रैंचरों (विशाल चारागाह के मालिक) और किसानों के बीच का अंतर्विरोध बहुत तीखा हुआ करता था, वहीं अब इस अंतर्विरोध से बहुत तीखा अंतर्विरोध पूंजीपतियों-विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और मजदूर वर्ग के बीच का अंतर्विरोध हो गया है। समूचे लातिन अमरीका में शहरीकरण की रफ्तार बहुत तेज रही है। इन देशों की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा द्वितीयक यानी उद्योग व तृतीयक क्षेत्र के योग से काफी कम है। ये देश अब मूलतया पूंजीवादी देशों में तब्दील हो चुके हैं। मौजूदा पूंजीवादी लातिन अमरीकी देशों में एक तरफ मुट्ठीभर अरबपति पूंजीपति है, जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के ताने-बाने से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ, दरिद्रता में डूबे मजदूर हैं जो संरक्षण देने वाले श्रम कानूनों से वंचित हैं तथा जिन्हें इन देशों की शहरी अर्थव्यवस्था के बढ़ते हुए अनौपचारिक क्षेत्र में शरण मिली हुई है, जिसका एक हिस्सा निरंतर नीचे धकेला जा रहा है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, समाजवाद की मौजूदगी, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों के ज्वार और अंतर साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा ने लातिन अमरीकी देशों के शासक पूंजीपति वर्ग को अपने मुनाफे बढ़ाने के नये अवसर दिये थे।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतें कमजोर हो गयी थीं। लातिन अमरीका में उनका प्रभाव लगभग न के बराबर रह गया था। यह क्षेत्र अमरीकी साम्राज्यवादियों के लिए खुला चारागाह बना हुआ था। लेकिन यही वह समय था जब एशिया और अफ्रीका के देशों में राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों का ज्वार आया हुआ था। इन मुक्ति संघर्षों का

प्रभाव लातिन अमरीकी देशों पर भी पड़ रहा था। 1959 की क्यूबा की क्रांति ने समूचे लातिन अमरीका पर असर डाला। इन सभी देशों में किसी न किसी रूप में क्रांतिकारी संघर्ष चलते रहे। शीत युद्ध के दौरान अमरीकी साम्राज्यवादी इस समूचे क्षेत्र में कम्युनिज्म का हौवा खड़ा करके अपनी खुली व छिपी दखलंदाजी करते रहे और यहां के शासकों को अपने नव-औपनिवेशिक शिकंजे में कसने की कोशिश करते रहे। लातिन अमरीकी देशों के शासक समय-समय पर इस नव-औपनिवेशिक शिकंजे से बाहर आने की कोशिश करते थे, लेकिन अमरीकी दखलंदाजी से उन्हें सत्ताच्युत कर दिया जाता था। दुनिया उपनिवेशवाद के चरण से होते हुए नव-उपनिवेशवाद के काल को भी पीछे छोड़ चुकी थी। लातिन अमरीकी देश इसका अपवाद नहीं हो सकते थे। विशेष तौर पर 1980 के दशक में लातिन अमरीकी देश जब भीषण कर्ज जाल में फंस गये थे, तब से इन देशों के शासक वर्ग के भीतर के अंतर्विरोध सतह पर आने लगे।

आज साम्राज्यवाद के युग के भीतर औपनिवेशिक चरण बीत चुका है, नव-औपनिवेशिक चरण भी मूलतः समाप्त हो चुका है। अब दुनिया साम्राज्यवाद के युग के भीतर आर्थिक नव-औपनिवेशिक चरण में है, जिसमें साम्राज्यवाद मुख्यतया अपनी आर्थिक ताकत के जरिये इन देशों में अपनी लूट और नियंत्रण करने की कोशिश करता है। इस आर्थिक ताकत के पीछे राजनीतिक और सामरिक ताकत लगी रहती है। साम्राज्यवादी राजनीतिक और सामरिक ताकत का इस्तेमाल करके अपनी आर्थिक लूट और राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लातिन अमरीका में अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष राजनीतिक व सैनिक हस्तक्षेप के अनेक उदाहरण हैं।

साम्राज्यवाद के युग के अंतर्गत आर्थिक नव-उपनिवेशवादी चरण का एक अन्य पहलू है। इस चरण ने एशिया, अफ्रीका, लातिन अमरीका के देशों को मुख्यतया स्वतंत्र देशों में तब्दील कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि इन देशों का शासक वर्ग राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र देश का शासक है। लेकिन यह अर्थिक तौर पर साम्राज्यवाद पर निर्भर है। यह स्वतंत्रता अलग-अलग देशों के शासक वर्ग के लिए अलग-अलग मात्रा में हो सकती है। यह कई कारणों यथा- उस देश की भू-राजनीतिक स्थिति, उसके आकार, संसाधन, वहां के राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष में पूंजीपति वर्ग की भूमिका इत्यादि, पर निर्भर करती है।

लातिन अमरीका के देशों ने अधिकांशतः उन्नीसवीं सदी में औपचारिक दासता से मुक्ति हासिल कर ली थी। यहां पर पूंजीपतियों, रेंचरों (बड़े चारागाहों के मालिक), बड़े भूस्वामियों, खदान मालिकों का शासन- संक्षेप में पूंजीपति वर्ग और बड़े भू-स्वामियों का शासन चलता रहा है। पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवाद के साथ घनिष्ठता के साथ जुड़ा रहा है। यह पूंजीपति वर्ग राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल अपने वर्ग स्वार्थों को आगे बढ़ाने के लिए करता रहा है। यह साम्राज्यवादियों के बीच के अंतरविरोध का इस्तेमाल भी अपने वर्ग-स्वार्थों के लिए करता रहा है। यह मजदूर -मेहनतकश वर्गों के संघर्षों से डरता है और इनका इस्तेमाल साम्राज्यवादियों के साथ रियायतें पाने के लिए सौदेबाजी में करता है। इस तरह, इसका चरित्र राष्ट्रीय सुधारवादी पूंजीपति वर्ग का है।

राष्ट्रीय सुधारवादी बुर्जुआ वर्ग के धड़े, साम्राज्यवाद के युग के अंतर्गत आर्थिक नव-उपनिवेशवाद के चरण में जन-असंतोष व जन-विद्रोह का इस्तेमाल करते हुए सत्ता में आने पर कुछ लोक लुभावनी परियोजनाएं लागू कर सकते हैं। वे कुछ आंसू पोछने वाली कार्यवाहियां कर सकते हैं। लेकिन इनका समाजवाद से कोई रिश्ता नहीं है। वे उत्पादन के साधनों की निजी मालिकाने की व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकते। यह उनके वर्ग-स्वार्थों के विरुद्ध है।

1980 के दशक से लातिन अमरीकी देशों में लागू की गयी नीतियों के परिणामस्वरूप वहां की मजदूर-मेहनतकश जनता का जीवन कठिन से कठिनतर होता गया। अलग-अलग देशों में लोग संघर्षों में आगे बढ़ने लगे। राष्ट्रीय सुधारवादी बुर्जुआ वर्ग की परम्परागत पार्टियों से मजदूर मेहनतकश जनता का मोहभंग हो चुका था। कई देशों में सैनिक तानाशाही के विरोध में लोग खड़े हो गये थे। इन देशों में जन असंतोष और गुस्से को अभिव्यक्ति देने वाले स्थानीय व देशव्यापी पैमाने पर अलग-अलग संगठन अस्तित्व में आ गये थे।

लातिन अमरीकी देशों में कम्युनिस्ट आंदोलन और मजदूर आंदोलन काफी पुराना होने के बावजूद 1970 के दशक से बहुत कमजोर हो चुका था। ख्रुश्चोवी संशोधनवाद का प्रभाव इन देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों पर था और अधिकांश पार्टियां शासक वर्ग के इस या उस हिस्से के साथ नत्थी होते हुए अप्रासंगिक होती गयीं। क्यूबाई क्रांति के प्रभाव में पैदा हुए चे-गुएरा के अनुयायी भी 1970 के दशक के अंत तक अलग-अलग देशों में प्रभावहीन हो चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में संशोधनवाद के प्रभावी होने और समाजवादी देशों में पूंजीवादी पुनर्स्थापना होने का प्रभाव लातिन अमरीका के कम्युनिस्ट आंदोलन पर भी पड़ा। आज स्थिति यह है कि पेरू को छोड़कर अधिकांश लातिन अमरीकी देशों में कम्युनिस्ट क्रांतिकारी छोटे-छोटे समूहों में विभाजित हैं। मजदूर आंदोलन भी सुधारवाद-अर्थवाद के दलदल में फंसा हुआ है। मजदूर आंदोलन पर शासक वर्ग की विचारधारा ही प्रभावी नहीं है बल्कि उनके संगठनों पर भी शासक वर्ग का प्रभुत्व है।

ऐसी स्थिति में जब मजदूरों-मेहनतकशों का शासक वर्गों के विरुद्ध जन असंतोष, गुस्सा और बेचैनी बढ़ रही हो, लोग अपने गुस्से का इजहार करने के लिए बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर रहे हों, लेकिन उनके गुस्से व उभार को नेतृत्व प्रदान करने के लिए कोई कम्युनिस्ट नेतृत्व न हो, तब उनके गुस्से, उभार व विद्रोह को पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर ही समेटने के लिए पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि आगे आयेंगे। चूंकि परम्परागत पूंजीवादी पार्टियां मजदूर-मेहनतकश अवाम के बीच बेनकाब हो चुकी हैं, इसलिए उनके बीच से नये चेहरे और नयी पार्टियां अगुवायी करेंगी। वे मेहनतकश अवाम के बीच अपने जनाधार को बनाने व बढ़ाने के लिए कुछ सुधारवादी कदमों को लागू करेंगी तथा साम्राज्यवाद और पूंजीवाद के विरोध में बोलेंगी।

लातिन अमरीकी देशों में पिछले एक दशक से आये 'वामपंथी' उभार की यही असलियत है। चिली, वेनेजुएला, ब्राजील, अर्जेन्टाइना, बोलीविया, इक्वाडोर, निकारागुआ और उरुग्वे में 'वामपंथी' कही जाने वाली सत्ताएं आयी हैं। इनमें सभी जन असंतोष और जन उभार के बाद चुन कर सत्तासीन हुई हैं। लोकरंजक नारे और सुधारवादी कार्यक्रम इनके चरित्र के अभिन्न अंग हैं। यह 'वामपंथी' उभार सिर्फ उन्हीं देशों तक सीमित नहीं है, जिन पर ऐसे 'वामपंथी' नेता सत्तासीन हुए हैं। इनका प्रभाव समूचे लातिन अमरीकी देशों में है। मैक्सिको में ओब्रेडोर को गलत तरीके से चुनावों में पराजित किया जाना और चुनावी धोखाधड़ी के विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन इसी का प्रभाव है।

यहां हम कुछ देशों की चर्चा करेंगे। विशेष तौर पर वेनेजुएला के ह्यूगो चावेज की सरकार की पड़ताल विस्तार से करेंगे। ह्यूगो चावेज की सरकार के बारे में वामपंथी बुद्धिजीवियों से लेकर कुछ कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के बीच काफी विभ्रम मौजूद हैं।

ब्राजील में लूला की सरकार

लातिन अमरीका में ब्राजील एकमात्र ऐसा देश रहा है, जिस पर पुर्तगाली उपनिवेशवादियों का आधिपत्य था। 1822 में राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद भी ब्राजील पुर्तगाल सम्राट के जरिये ही शासित होता था। 1889 में सैनिक तख्तापलट के बाद वह गणतंत्र बना। 1889-1930 के दौरान वह गणतंत्र रहा। 1930 में तख्तापलट हुआ और पुराने गणतंत्र का अंत हो गया। 1930 से 1945 तक वार्गास राष्ट्रपति रहा। 1945 में सैनिक तख्तापलट के जरिये जनरल यूरिको गास्पर दुत्रा सत्ता में आया। 1951-54 तक वार्गास दुबारा सत्तासीन हुआ। वार्गास द्वारा आत्महत्या कर लेने के बाद गौलार्ट राष्ट्रपति हुआ। 1964-85 तक सैनिक तानाशाही रही। 1986 के बाद से नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के प्रवक्ता राष्ट्रपति थे। इस प्रकार, हम देख सकते हैं कि ब्राजील में या तो सैनिक तानाशाही रही है या फिर राजनीति में ऊपरी तबके के लोग, जो अधिकांश अनुदारवादी थे, सत्ता में रहे हैं।

ब्राजील लातिन अमरीका में ही सबसे बड़ा देश नहीं बल्कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह संयुक्त राज्य अमरीका से थोड़ा ही छोटा है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी अर्थव्यवस्था अर्जेन्टाइना से तीन गुना बड़ी है। यहां प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। उपजाऊ जमीन है। लोहे और अन्य खनिज सम्पदा के भंडार हैं। यूरेनियम और पेट्रोलियम के भंडार हैं।

लूला के सत्ता में आने के पहले यहां कारडोसो की सरकार ने 'वाशिंगटन कन्सेन्सस' की नीतियों को लागू किया था। वाशिंगटन कन्सेन्सस (Washington Consensus) शब्द को अंग्रेज अर्थशास्त्री जॉन विलियम्स ने 1990 में गढ़ा था। इसके तहत उसने गरीब मुल्कों के विकास के लिए आवश्यक दस नीतियों को लागू करने की सिफारिश की : 'राजकोषीय अनुशासन', सार्वजनिक व्यय का पुनर्नियोजन, कर सुधार, वित्तीय उदारीकरण, प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय दरें, व्यापार उदारीकरण, विदेशी निवेश में खुलापन, निजीकरण, विनियमन (Deregulation) और सम्पत्ति अधिकारों की सुरक्षा (Preservation)। 'वाशिंगटन कसेन्सस' की नीतियों को लागू करने के बाद ब्राजील एक के बाद दूसरे संकट में फंसता चला गया। लूला की वर्कर्स पार्टी (पुर्तगाली भाषा के अक्षरों में पी.टी.) ने पुरानी नीतियों को उलट कर नयी आर्थिक नीतियों को लागू करने की बात की। लेकिन सरकार में आने से पहले ही लूला ने जून 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विदेशी कर्ज के भुगतान करने, बजट अधिशेष को 4% पर कायम रखने (जिसे बाद में बढ़ा कर 4.5% तक करना होता), वृहद आर्थिक स्थायित्व (Macro Economic Stability) को बनाये रखने तथा नव-उदारवादी सुधारों को जारी रखने के बारे में एक समझदारी के पत्र (memorandum of understanding) पर हस्ताक्षर किये थे। सरकार में आने के बाद उसने सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के पेंशन में 30% कटौती कर दी और यह दम्भपूर्ण घोषणा की, कि उसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के "सुधारों" को लागू करने में जो "साहस" दिखाया है, वह पहले के दक्षिणपंथी राष्ट्रपति करने में असफल हो गये थे। पूंजी निवेश का प्रोत्साहित करने के लिए लूला ने ऐसे श्रम कानूनों को लागू किया जिससे मजदूरों

को निकालने और निकाले जाने के एवज में मिलने वाली रकम की मात्रा को कम करने में नियोजकों की शक्ति बढ़ जाय। सत्ता में आने के बाद तीन शुरुआती वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा के सामाजिक कार्यक्रमों का घटाकर 5% के करीब कर दिया। लेकिन विदेशी कर्जदाताओं को समय से (और यहां तक कि समय से पहले ही) 100 अरब डॉलर का भुगतान कर दिया। इस तरह, उसने ब्राजील को एक 'मॉडल' कर्जदार सिद्ध कर दिया।

पेट्रोब्रास पेट्रोल कम्पनी, खदानों और बैंकों का निजीकरण तो पिछली सरकारों ने किया था। लूला दक्षिणपंथी सरकारों से इस मामले में भी पीछे रहने वाले नहीं थे। उन्होंने अवरचना, सेवा और दूरसंचार क्षेत्रों का निजीकरण कर दिया। निर्यात में प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, जबकि औद्योगिक क्षेत्र दुनिया की ऊंची ब्याज दरों और कम तट करों के कारण ठहराव का शिकार बना रहा। समूचे लातिन अमरीका में ग्वाटेमाला के बाद ब्राजील सबसे अधिक असमानता वाला देश बना रहा।

कृषि उत्पाद निर्यात को मदद देने और उसे सब्सिडी देने पर कृषि नीति केन्द्रित रही, जब कि कृषि सुधार कार्यक्रम या तो वैसे ही पड़े रहे या पीछे की ओर गये। लूला को सत्तासीन करने में मदद पहुंचाने वाले सहयोगी संगठन के साथ किये गये वायदों को उसने किस तरह पूरा किया यह एम.एस.टी. (भूमिहीन मजदूर आंदोलन) द्वारा लूला सरकार को लगातार दी जाने वाली चेतावनी से समझा जा सकता है। लूला ने भूमिहीन मजदूर आंदोलन से यह वायदा किया था कि सत्ता में आने के एक साल के भीतर एक लाख परिवारों को जमीन वितरित की जायेगी। इसकी पूर्ण अवहेलना की गयी। लूला के शासन के अंतर्गत एक साल में महज 25000 परिवारों को ही जमीन दी गयी। 45 लाख भूमिहीन परिवार अब भी बिना किसी आशा के पड़े हुए हैं।

विदेशी नीति के मामले में लूला ने हैती में चुने गये राष्ट्रपति अरिस्टाइड को अमरीकी साम्राज्यवादियों की साजिश से हटाये जाने के बाद बनी कठपुतली सरकार की रक्षा के लिए सेना और कर्मचारी भेजे।

लूला डि-सिल्वा ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपना उपराष्ट्रपति जोस एलन्कार नाम के एक पूंजीपति को बनाया। हालांकि उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और उसे बाद में इस्तीफा देना पड़ा। लूला पूंजी और श्रम के बीच सामाजिक समझौते की बात करते हैं।

लूला की पार्टी और सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण वर्कर्स पार्टी के कई शीर्ष पदाधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ा है। लूला के नजदीकी कई सांसदों को भी इस्तीफा देना पड़ा है।

इस प्रकार, हम देख सकते हैं कि लूला की सरकार कृषि, उद्योग, विदेश नीति, मजदूरों के बारे में नीति सभी में अपने मूल मंत्र- श्रम और पूंजी के बीच सामाजिक समझौते- के तहत चल रही है।

एक तरफ, जहां लूला की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा निर्देशित नव-उदारवादी नीतियों को लागू कर रही है वहीं दूसरी तरफ, राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधिमूलक जनतंत्र (Representative Democracy) को सहभागी जनतंत्र (Participatory Democracy) से समृद्ध करने, सहभागी बजट तैयार करने (Participatory Budgeting), सामाजिक आंदोलनों इत्यादि की स्वयत्तता की बातें कर रही है और इन्हें एक हद तक लागू कर रही है।

इसके अलावा, वह दक्षिण अमरीकी देशों के व्यापार संघ 'मरकोसूर' में भूमिका निभाकर अमरीकी प्रभुत्व के विरुद्ध एक व्यापार संघ बना रही है। एशिया, अफ्रीका के देशों के साथ अपने सम्बन्ध प्रगाढ़ कर रही है।

लूला के इन कदमों से उसके वर्ग चरित्र को समझा जा सकता है। ब्राजीली समाज के शीर्ष में बैठे पूंजीपति वर्ग और बड़े भूस्वामियों की स्थिति में बगैर कोई बुनियादी तब्दीली किये हुए वह ब्राजील के मजदूरों, भूमिहीनों तथा समाज के अन्य मेहनतकश तबकों की स्थिति में कुछ सुधार करना चाहता है। वह अमरीकी साम्राज्यवाद के प्रभुत्व से ब्राजील को छुटकारा दिलाने की बातें करता है। इस अर्थ में वह ब्राजील के ऐसे पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है जिसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की आकांक्षा है। लेकिन लोकप्रिय आंदोलन की उपज होने के कारण तथा मजदूर वर्ग के भीतर सामाजिक आधार के चलते उसे अपने सामाजिक आधार के लिए कुछ लोकरंजक कदम उठाने पड़ते हैं। इससे उसके परस्पर विरोधी कदमों को समझा जा सकता है।

विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के अभिन्न अंग रहते हुए न तो ब्राजीली समाज साम्राज्यवादी वर्चस्व से मुक्त हो सकता है और न ही उसे पूंजीवाद से मुक्ति मिल सकती है। यह लूला और उसकी पार्टी अच्छी तरह समझती है।

लूला की वर्कर्स पार्टी (पी.टी.) दुनिया के पैमाने पर विश्व सामाजिक मंच (World Social Forum) के माध्यम से 'एक नयी दुनिया सम्भव है' के नारे की फेरी लगा रही है। यह मंच तरह-तरह के सामाजिक संगठनों और गैर सरकारी संगठनों (NGO's) द्वारा 'विचार-विमर्श' करने तथा अपने अनुभवों का आदान प्रदान करने के नाम पर आई.एम.एफ. और विश्व बैंक द्वारा निर्देशित 'वैश्वीकरण' के विरुद्ध बनाया गया है। यह साम्राज्यवादी संस्थाओं के वित्त द्वारा पालित-पोषित है। यह 'मंच' कोई संगठन नहीं है जो वैश्वीकरण के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए बना हो। न तो यह संघर्ष करने के बारे

में कोई फैसला लेता है और न ही यह दुनिया भर में चल रहे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों के बीच समन्वय कायम करता है। यह महज 'विचार-विमर्श' करता है। लूला की पार्टी (वर्कर्स पार्टी) किस तरह से साम्राज्यवाद- पूंजीवाद का विरोध करना चाहती है, यह इस मंच में उसकी अग्रणी भूमिका से भी समझा जा सकता है।

लूला सरकार की से सारी कवायदें सुधारवादी बुर्जुआ वर्ग की सरकार की कवायदें हैं जो अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए लोकरंजक कदम उठाती है तथा पूंजीवादी व्यवस्था के कोढ़ से ग्रस्त सड़े-गले शरीर को रामनामी चादर से ढंकने का प्रयास करती है।

वेनेजुएला में चावेज की सरकार

बीसवीं सदी के शुरू से ही, वेनेजुएला एक बड़ा तेल उत्पादक देश रहा है। इसके तेल और प्राकृतिक गैस पर अमरीकी तेल कम्पनियों का नियंत्रण रहा है। अमरीका की तेल जरूरतों का करीब 15-16% वेनेजुएला पूरा करता है। इसलिए अमरीका वेनेजुएला की राजनीति में दखलंदाजी और यहां तक कि तख्तापलट कराने की कोशिश करता रहा है। अमरीकी साम्राज्यवादियों ने 1948 में सैनिक तख्तापलट के जरिये वहां की सरकार को हटा दिया था। 1958 में पीरेज जिमनेज की तानाशाही के विरुद्ध एक सैनिक विद्रोह हुआ जिसकी अगुवाई फाब्रिसिओ ओडेजा ने की थी। इस विद्रोह के समर्थन में वहां की दोनों बड़ी पूंजीवादी पार्टियां ए.डी. (डेमोक्रेटिक एक्सन) (स्पैनिश में Accion democratia) और सी. ओ.पी.ई.आई. (स्पैनिश में Comite de organizacion politica Electoral Independiente-COPEI) थीं तथा उनका समर्थन व सहयोग उस समय वेनेजुऐला की संशोधनवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था। 1958 में ही सैनिक विद्रोह के नेताओं और राजनीतिक दलों के बीच समझौता हुआ था जिसे पुस्टो फिजो पैक्ट कहा जाता है, जिसके तहत दोनों बड़ी पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता में भागीदारी करने पर समझौता हुआ। 1958 से अब तक वहां की राजनीतिक पार्टियां सरकार चलाती रही हैं। लेकिन समय-समय पर सैनिक विद्रोह भी होते रहे हैं। इसके साथ ही वेनेजुएला की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में चलने वाले छापामार संघर्ष भी चलते रहे हैं। लेकिन छापामार संघर्ष 70 के दशक तक आते-आते ठप्प पड़ गये थे।

ह्यूगो चावेज ने सेना के भीतर 1982 में बोलीवारियाई क्रांतिकारी आंदोलन -200 (MBR-200) नाम से संगठन बनाया था। 1998 में सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित ढांचागत सुधार कार्यक्रम चलाये गये। इसके तहत बदलती हुई ब्याज दरें, सार्वजनिक सेवाओं में बढ़े हुए कर, आयात तट करों में क्रमशः बढ़ोत्तरी, बजट घाटे में 4% की कटौती, श्रम कानूनों में परिवर्तन, विदेशी कम्पनियों को अपने लाभ का 100% बाहर अपने देश ले जाने की छूट दी गयी। इस दौरान मुद्रास्फीति 80.7% बढ़ गयी, वास्तविक वेतनों में 40% की गिरावट आयी, बेरोजगारी 14% बढ़ गयी और 80.42% आबादी गरीबी में जीवन बसर कर रही थी।

जनता की बढ़ती गरीबी और गैस की कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप 1998 में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। इस व्यापक जन उभार को सेना ने कुचल दिया। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार, इस उभार में सेना द्वारा 5000 लोग मार दिये गये। समूचे देश में सेना ने कहर बरपा किया।

ह्यूगो चावेज 1992 में कारलोस एण्ड्रीज पेरेज की सरकार के विरुद्ध असफल सैनिक बगावत के बाद राष्ट्रीय पटल पर चर्चा का विषय बन गये थे। 1994 में जेल से छूटने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में 1998 में विजय हासिल की।

1998 में चावेज के सत्ता में आने से पहले वेनेजुएला में 1958 के बाद से आने वाली सरकारें भ्रष्टाचार में डूबी हुई थीं। आर्थिक और सामाजिक असमानता व्यापक थी और वह बढ़ती जा रही थी। आबादी के 2% लोगों के पास 60% जमीन का मालिकाना था। 80% आबादी गरीबी में जीवन बसर करती थी। वेनेजुएला की राष्ट्रीय तेल कम्पनी पी.डी.वी. एस.ए. (Peroleos de Venezuela -PDVSA) 'राज्य के भीतर एक राज्य' थी। उस पर वेनेजुएला सरकार का नाममात्र का नियंत्रण था। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ता जा रहा था। अमरीकी साम्राज्यवादी वेनेजुएला के तेल पर काफी हद तक निर्भर थे। पहले जब भी ओपेक तेल के दाम बढ़ाने की कोशिश करता था तो वेनेजुएला इसे रोक देता था। इससे वेनेजुएला पर अमरीकी साम्राज्यवादियों के प्रभाव को समझा जा सकता है, क्योंकि इससे अमरीकी साम्राज्यवादियों को सस्ते में तेल मिल जाता था।

1998 में जब चावेज सत्तासीन हुए तो उन्होंने नव उदारवाद को वेनेजुएला की तमाम आर्थिक व सामाजिक समस्याओं की जड़ बताया। उन्होंने आर्थिक विकास के 'तीसरे रास्ते' को लागू करने की बात की। 1999 में उन्होंने नया

संविधान तैयार किया जिसमें सार्वजनिक कल्याण का विस्तार करने और श्रमिकों की सुरक्षा को शामिल किया गया। इसके साथ ही तेल कम्पनी पी.डी.वी.एस.ए. के निजीकरण की प्रक्रिया को रद्द किया गया। विदेशी तेल कम्पनियों, एक्सोन मोबिल और अन्यों पर रॉयल्टी लगभग 16% से बढ़ाकर 30% के आसपास कर दी गयी। उन भूस्वामियों पर, जो 80% से ज्यादा जमीन पर खेती नहीं करते, निष्क्रियता कर लगाने तथा जमीनों की सम्भावित जब्ती की बात की गयी। ये सारी नीतियां अमरीकी साम्राज्यवाद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नुस्खों के विपरीत जाती थीं। सन् 2002 में पूंजीपतियों के संगठन के अध्यक्ष पेड्रो कारमोना एस्टांगा ने घोषणा कर दी कि चावेज ने इस्तीफा दे दिया है, कि वह खुद संक्रमण कालीन सरकार का नेतृत्व करेंगे। कारमोना की इस संक्रमणकालीन सरकार में बैंकर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष और वेनेजुएला के सबसे बड़े मीडिया समूह के मुखिया को मंत्री बनाया गया। कारमोना ने तुरंत संसद को भंग कर दिया और भूमि सुधार तथा तेल सुधार नीतियों को रद्द कर दिया। इस सत्ता पलट में सेना के कुछ अधिकारियों की भूमिका थी और उन्होंने चावेज को एक जगह नजरबंद कर दिया। इस सत्ता दखल के विरुद्ध व्यापक विरोध हुए और 48 घंटे के भीतर चावेज पुनः सत्तासीन हो गये। इस तख्तापलट के पीछे मुख्य तौर पर अमरीकी साम्राज्यवादी थे।

अप्रैल, 2002 के इस तख्तापलट के बाद अमरीकी साम्राज्यवादियों ने तुरन्त कारमोना की सरकार को मान्यता दे दी। लातिन अमरीका के अधिकांश देशों ने कारमोना की सरकार को मान्यता नहीं दी। पश्चिमी गोलार्द्ध में सिर्फ अल-सल्वाडोर की सरकार ने इसे मान्यता दी थी। अमरीकी राज्यों के संघ (ओ.ए.एस.) ने तख्तापलट को असंवैधानिक करार देते हुए इसकी निंदा की।

तख्तापलट की कार्यवाही में असफल होने के बाद विरोधी पूंजीवादी पार्टियां और ज्यादा सक्रिय हो गयी। उन्होंने राज्य तेल कम्पनी पी.डी.वी.एस.ए. के मैनेजरों के जरिए हड़तालों की श्रृंखला लगा दी। उनके इस कार्य में दलाल ट्रेड यूनियन सी.टी.वी. की प्रमुख भूमिका थी। 2002-2003 की इन हड़तालों से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। लेकिन लोगों का असंतोष चावेज के विरोध में जाने के बजाय विरोधी पूंजीवादी पार्टियों के विरुद्ध ही गया।

अमरीकी साम्राज्यवाद विरोधी इन कदमों के अलावा चावेज सरकार ने देश के भीतर साक्षरता फैलाने, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने तथा झुग्गी-झोंपड़ियों (शैन्टी टाउन्स) में लोगों की मकान बनाने में मदद करने, छोटा उधार उपलब्ध कराने (Micro finance), बंद पड़ी फैक्टरियों में मजदूरों द्वारा प्रबन्धन कराने के साथ भूमि सुधार के कार्यक्रम को लागू किया।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मामले में उसने लातिन अमरीकी देशों के बीच आपसी सहकार को आगे बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिये हैं। वह 'मरकोसूर' का सदस्य बन गया। लातिन अमरीकी देशों को सस्ते में तेल उपलब्ध कराया है। अमरीका द्वारा पेश इस क्षेत्र के लिए अमरीकी मुक्त व्यापार क्षेत्र के विरोध में बोलीवारियन व्यापार क्षेत्र की स्थापना की पेशकश की है। क्यूबा से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध रखने तथा अमरीका द्वारा अफगानिस्तान और इराक पर हमले व कब्जे की सार्वजनिक तौर पर और हर मंच से भर्त्सना की।

उसके ये सारे कदम अमरीकी साम्राज्यवादियों के हितों के विरुद्ध हैं। अमरीकी सरकार की कई सारी खुफिया एजेन्सियां वेनेजुएला के भीतर तोड़-फोड़ करने और चावेज की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही हैं।

इतने सारे सुधारवादी कदमों को उठाने वाले और अमरीकी साम्राज्यवाद के विरोधी चावेज का वर्ग चरित्र क्या है? यह समझने के लिए उसके विचारधारात्मक आधार और वर्ग-दृष्टिकोण को समझना जरूरी है।

चावेज जगह-जगह अपने भाषणों में और साक्षात्कारों में 1970 के दशक की दुनिया में लौटने की बात बार-बार करते हैं। उनकी दृष्टि से जब तीसरी दुनिया के देश एक नयी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग कर रहे थे, उस समय यदि यह मांग पूरी हो जाती तो दुनिया न्यायसंगत हो जाती। चावेज के अनुसार, आज यदि नयी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली लागू हो तो साम्राज्यवाद का अस्तित्व खत्म हो जायेगा। उस समय नयी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग के द्वारा तीसरी दुनिया का शासक वर्ग, साम्राज्यवादी देशों द्वारा तीसरी दुनिया से लूटे अधिशेष का एक हिस्सा तीसरी दुनिया में अनुदान के बतौर देने तथा तीसरी दुनिया के देशों के लिए व्यापार की ज्यादा अनुकूल शर्तों की मांग कर रहा था। यानी, तब भी साम्राज्यवादी देशों और तीसरी दुनिया के देशों के बीच सम्बन्ध असमानता पर ही आधारित होते और यह साम्राज्यवादी व्यवस्था के भीतर सम्भव है। इसी तरह, उस समय का गुट निरपेक्ष आंदोलन या अफ्रीकी-एशियाई देशों का बांदुंग सम्मेलन, इसी मांग पर केन्द्रित था कि साम्राज्यवादी देशों से नव-स्वाधीन देश मिलकर सौदेबाजी करके अपनी स्थिति को थोड़ा बेहतर कर सकें।

इसी प्रकार, उसके वेनेजुएला के भीतर सारे सुधारवादी कदम 'कल्याणकारी राज्य' के दायरे में आते है। यह सही है कि नवउदारवादी कदमों की तुलना में ये मेहनतकश आबादी के एक हिस्से को एक हद तक राहत देने वाले कदम हैं। लेकिन ये सारे कदम पूंजीवादी दायरे में आते हैं।

चावेज का अमरीकी साम्राज्यवाद के वर्चस्व का मुखर विरोध समझ में आता है। और वह न्यायसंगत है। क्योंकि वेनेजुएला सहित समूचे लातिन अमरीका में अमरीकी सम्राज्यवादियों का प्रभुत्व स्थापित है और चावेज व्यापक मेहनतकश आबादी के न्यायसंगत गुस्से को ही अभिव्यक्ति दे रहे हैं। लेकिन चावेज का साम्राज्यवादी-पूंजीवादी विश्व व्यवस्था से कोई बुनियादी विरोध नहीं है।

पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास का पूंजीवादी दायरे में एक सपना मशहूर लातिन अमरीकी अर्थशास्त्री राउल प्रेब्रिश ने देखा था। लातिन अमरीकी देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साम्राज्यवाद के साथ रिश्तों से और लातिन अमरीकी शासकों की फिजूलखर्ची इत्यादि से वहां के आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है, ऐसा उनका विश्लेषण था। इसके लिए उन्होंने आयात प्रतिस्थापन-औद्योगीकरण की प्रक्रिया को लागू करने का सुझाव दिया था। ह्यूगो चावेज के नुस्खे उनसे अभी बहुत पीछे के हैं।

चावेज की राजनीति की परियोजना कहीं से भी न तो पूंजीवाद विरोधी है और न ही साम्राज्यवाद से एक व्यवस्था के बतौर उनका कोई बुनियादी विरोध है। हां, उनका विरोध नव उदारवादी नीतियों और अमरीकी साम्राज्यवाद के प्रभुत्ववाद से है।

इस तरह, चावेज वेनेजुएला के ऐसे राष्ट्रीय सुधारवादी पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि हैं, जो औद्योगिक विकास में साम्राज्यवाद से लाभ तो लेना चाहता है लेकिन उसके शिकंजे में फंसना नहीं चाहता।

ह्यूगो चावेज के 'इक्कीसवीं सदी के समाजवाद' का विचारधारात्मक आधार उन्नीसवीं सदी के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता सीमोन बोलीवार हैं, जिनके विचारों का समाजवाद से दूर-दूर का रिश्ता नहीं है। चावेज के प्रेरणा स्रोत पनामा के जनरल ओमार टोर्रोजोस तथा पेरू के जनरल अल्वाराडो की 'क्रांतिकारी सैनिक सरकार' है। यह उनकी खुद की स्वीकारोक्ति है। वह खुद निजी सम्पत्ति के समर्थक हैं। उनका 'समाजवाद' या 'तीसरा रास्ता' निजी सम्पत्ति पर आधारित व्यवस्था ही होगा।

ह्यूगो चावेज व्यक्तिगत लोकप्रियता के आधार पर सत्तासीन हुए हैं। अपने सैनिक जीवन में सेना के अफसरों के बीच गुप्त प्रचार करके उन्होंने पहले संगठन का जाल खड़ा किया फिर सत्ता में आने के बाद वे उन्हीं कार्यरत या सेवानिवृत्त फौजी अफसरों के जरिये अपने कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं। न तो खुद ह्यूगो चावेज किसी मजदूर आंदोलन की उपज हैं और न ही वे जो संगठन खड़ा कर रहे हैं वह किसी मार्क्सवाद-लेनिनवाद पर आधारित है। अतः उनके 'इक्कीसवीं सदी के समाजवाद' का वैज्ञानिक समाजवाद से कुछ भी लेना-देना नहीं है।

ह्यूगो चावेज उसी नौकरशाही, फौज, न्यायपालिका के माध्यम से, यानी उसी पूंजीवादी राज्य मशीनरी के माध्यम से 'समाजवाद' लाने की बात करते हैं जो पूंजीवाद की सेवा करने के लिए बनी है। पूंजीवादी व्यव्स्था के भीतर से समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध विकसित करने की बात या तो दिवास्वन है या फिर मजदूरों और व्यापक मेहनतकश जनता की आंख में धूल झोंकना है।

चावेज के बारे में भ्रम पैदा करने वाले कुछ 'वामपंथी'

कुछ वामपंथी कहे जाने वाले बुद्धिजीवी ह्यूगो चावेज के सत्ता में आने तथा उसके बाद के कदमों को बोलीवारियाई क्रांति कहते हैं। कुछ त्रात्स्कीवादी इसे राष्ट्रीय जनवादी क्रांति की संज्ञा देते हैं, जो त्रात्स्की की स्थायी क्रांति **(Permanent Revolution)** की अवधारणा की पुष्टि करते हुए समाजवादी क्रांति में तब्दील हो जायेगी। इन त्रात्स्कीपंथियों के अनुसार, वेनेजुएला अर्द्ध-उपनिवेश है और वहां ह्यूगो चावेज द्वारा निर्देशित बोलीवारियाई क्रांति, राष्ट्रीय जनवादी क्रांति है। इसी तरह के भ्रम के शिकार या भ्रम पैदा करने वाले कुछ कम्युनिस्ट क्रांतिकारी हैं जो ह्यूगो चावेज को कट्टर साम्राज्यवाद-विरोधी सिद्ध करने की कोशिश करते हैं।

'बोलीवारियाई क्रांति' क्या है? इसने किन सामाजिक वर्गों को सत्ताच्युत किया है? कौन से वर्ग सत्ता में आये हैं? ये 'क्रांतिकारी' इन स्पष्ट सवालों के जवाब गोलमोल ढंग से देते हैं। वे यह तो बताते हैं कि क्रांति में जनता की सक्रियता बहुत अधिक बढ़ जाती है, वह राजनीतिक मामलों में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करने लगती है। लेकिन यह नहीं बताते कि क्या पुराना शासक वर्ग सत्ताच्युत हो गया है? वे इस सवाल पर बगलें झांकने लगते हैं। तब वे कहते हैं कि क्रांति एक सतत् प्रक्रिया है और कि जब तक धनिक तंत्र की आर्थिक शक्ति को नहीं नष्ट कर दिया जाता, यानी कि जब तक कल-कारखाने, बैंक और बड़े भू-स्वामियों की जमीन पर कब्जा नहीं कर लिया जाता, तब तक क्रांति सम्पन्न नहीं होगी, क्रांति को प्रति-क्रांति पीछे धकेल सकती है। इस प्रकार, ये त्रात्स्कीपंथी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए ह्यूगो

चावेज के पीछे मजदूर वर्ग और अन्य मेहनतकश लोगों की ताकत को लगाने के लिए जुट गये हैं। खुद इनके अनुसार ह्यूगो चावेज एक निम्न पूंजीवादी राष्ट्रीय जनवादी क्रांतिकारी हैं और उनके आंदोलन का लक्ष्य पूंजीवादी जनवादी सीमाओं से आगे नहीं जाता। लेकिन ये ह्यूगो चावेज के बोलीवारियाई आंदोलन के पीछे मजदूर वर्ग की ताकत को झोंककर उन सीमाओं को तोड़ने की बात करते हैं।

पहली बात तो यह स्पष्ट हो लेने की जरूरत है कि ह्यूगो चावेज किसी क्रांतिकारी आंदोलन के बल पर सत्तासीन नहीं हुए। वे उसी पूंजीवादी राज्य के अंतर्गत होने वाले चुनावों के जरिए सत्ता में आये थे। उनके सत्ता में आने के पहले आम मजदूरों-मेहनतकशों के बीच व्यापक जन असंतोष, गुस्सा और बेचैनी फैली हुई थी। सत्ताधारी पार्टी के विरुद्ध गुस्से ने ह्यूगो चावेज को सत्तासीन करने में भूमिका निभायी। सत्ता में आने के बाद उन्होंने 1999 में नया संविधान पारित कराया। इस संविधान की 112वीं धारा ***निजी पहलकदमी को बढ़ावा देने*** के लिए राज्य का आह्वान करती है। इसी संविधान की 115वीं धारा सम्पत्ति के ***अधिकार की गारंटी*** करती है और 299वीं धारा आर्थिक वृद्धि और रोजगार बढ़ाने के लिए ***निजी पहलकदमी की भूमिका*** को रेखांकित करती है। इसके बाद, ह्यूगो चावेज की सरकार ने 2001-2007 के लिए योजना पारित की, जो निजी पूंजी, दोनों घरेलू और विदेशी, निवेश को प्रोत्साहित करने पर केन्द्रित रही है। हां इस योजना में अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों को 'सामाजिक अर्थव्यवस्था' में तब्दील करने का फैसला लिया गया। इसी तरह के गरीबों के आंसू पोछने वाले अन्य सामाजिक कार्यक्रम अपनाये गये।

1999 के संविधान में और अपने साप्ताहिक भाषणों में ह्यूगो चावेज जन हिस्सेदारी करने वाले जनतंत्र (Participatory Democracy) की बार-बार चर्चा करते हैं। 2007 के संविधान संशोधन की धाराओं से 'निम्न पूंजीवादी क्रांतिकारी' ह्यूगो चावेज का चरित्र स्पष्ट हो जाता है। इस प्रस्तावित संविधान संशोधन में निजी सम्पत्ति की 'पवित्र गाय' को बिल्कुल छुआ तक नहीं गया। राष्ट्रपति के चुनाव में दो बार राष्ट्रपति होने वाला व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, यह संशोधन प्रस्तावित था। इसके अलावा राष्ट्रपति की समयावधि बढ़ाने का भी प्रस्ताव था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति के पास अनिश्चित अवधि तक आपातकाल घोषित करने का अधिकार था जिसमें नागरिकों के अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निलंबित की जा सकती थी और इनकी ***पुनरीक्षा का अधिकार किसी न्यायालय*** को नहीं था। इस प्रस्तावित संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को संघीय क्षेत्रों को बदलने का अधिकार था, जिनसे सारतः राष्ट्रपति को प्रांतीय और नगरों में चुनी हुई सरकारों को हटाकर अपने मनोनीत लोगों द्वारा भरने तथा सेना के भीतर तरक्की देने के सभी अधिकार प्राप्त होते थे। ये संविधान संशोधन जनमत संग्रह में अत्यल्प बहुमत से ठुकरा दिये गये। इसके बाद भी, ह्यूगो चावेज इन संशोधनों में एक भी अर्द्ध-विराम तक बदलने को तैयार नहीं हैं।

त्रात्स्कीपंथियों सहित 'वामपंथी' बुद्धिजीवियों में कुछ लोग स्तालिन कालीन सोवियत संघ को समाजवादी देश नहीं मानते, बल्कि उसे 'नौकरशाही विकृतियों वाले मजदूर राज्य' या 'समाजवाद, जैसा कि वह था' जैसी संज्ञाओं से संबोधित करते हैं। लेकिन इनको ह्यूगो चावेज मेहनतकश जनता के प्रति 'ईमानदार', अमरीकी साम्राज्यवाद तथा अपने देश के धनिक तंत्र के विरुद्ध संघर्ष करने में 'साहसी' नजर आते हैं। सिर्फ इतना ही नही, वे 'इक्कीसवीं सदी में समाजवाद' के प्रस्तोता नजर आते हैं। इसलिए वे मजदूर वर्ग का आह्वान करते हैं कि ह्यूगो चावेज के हाथों को मजबूत करें। स्तालिन कालीन सोवियत संघ में पूंजीपति वर्ग को वर्ग के बतौर समाप्त कर दिया गया था। कृषि का सामूहिकीकरण हो चुका था। पुराने समाज के शोषक वर्ग समाप्त हो गये थे। नये समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध विकसित हो रहे थे। समूचा पूंजीवादी विश्व, साम्राज्यवादी दानव इसीलिए समाजवादी राज्य और उसके नेता स्तालिन से घोर नफरत करते थे। मजदूर आंदोलन के गद्दार भी स्तालिन से नफरत करते हैं। वे सोवियत समाजवादी राज्य को समाजवादी मानने तक को नहीं तैयार थे। आज उन्हीं मजदूर आंदोलन के गद्दारों और उनके पथगामियों को ह्यूगो चावेज निम्न पूंजीवादी क्रांतिकारी नजर आता है तथा उसके पीछे चलकर ये समाजवादी क्रांति को पूरा करने का सपना देखते हैं।

वास्तविकता यह है कि ह्यूगो चावेज अपने पूंजीवादी एजेण्डे पर चल रहे हैं। वे 'कल्याणकारी राज्य' के कुछ कार्यक्रमों को लागू कर रहे हैं। हां, वे यह सब ऐसे समय में कर रहे हैं, जब समूची दुनिया में इसके विरुद्ध तथा साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के पक्ष में नीतियां लागू हो रही हैं। लेकिन 'कल्याणकारी राज्य' भी एक पूंजीवादी राज्य है। मजदूर आंदोलन के ये गद्दार इसी बुनियादी बात को अपनी बहस से गायब कर देते हैं। तब इन त्रात्स्कीपंथियों के समक्ष ह्यूगो चावेज के बोलीवारियाई आंदोलन के साथ 'संयुक्त मोर्चा' बनाने के नाम पर उनके एजेण्डे के आधार पर मजदूर वर्ग को चावेज पीछे लामबंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता।

वे ह्यूगो चावेज के आंदोलन से वह उम्मीद जगाते हैं जो वह है ही नहीं। वे क्रांति के बारे में, ह्यूगो चावेज के आंदोलन के वर्ग-चरित्र के बारे में, खुद ह्यूगो चावेज के व्यक्तिगत गुणों के बारे में, ह्यूगो चावेज के अंतर्गत वेनेजुएला के राज्य के चरित्र के बारे में तथा इक्कीसवीं सदी के समाजवाद के बारे में बुनियादी तौर पर गलत प्रस्थापनायें पेश

करते हैं। इसके साथ ही, वेनेजुएला को अर्द्ध-उपनिवेश बताकर वे राष्ट्रीय जनवादी क्रांति की मंजिल का गलत मूल्यांकन पेश करते हैं।

वेनेजुएला अन्य लातिन अमरीकी देशों की तरह राष्ट्रीय सुधारवादी बुर्जुआ वर्ग के नेतृत्व में पूंजीवादी राज्य है। राष्ट्रीय सुधारवादी बुर्जुआ वर्ग अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ घनिष्ठता के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बुनियादी स्वार्थ अपने लिए ज्यादा सौदेबाजी करने में है। लेकिन अमरीकी साम्राज्यवादियों के इस देश में लम्बे समय से चले आ रहे प्रभुत्व के कारण पूंजीपतियों के लिए सौदेबाजी करने की ताकत अत्यन्त कमजोर रही है। दूसरे, अमरीकी साम्राज्यवादियों से सांठ-गांठ करके यह वर्ग क्रमशः और धनी हुआ है। इसी वर्ग की नीतियों के विरुद्ध व्यापक जन असंतोष पैदा हुआ और 1998 में ह्यूगो चावेज ने अमरीकी साम्राज्यवाद और आई.एम.एफ. तथा विश्व बैंक द्वारा प्रस्तावित नव उदारवादी नीतियों का विरोध करके लोकरंजक नारों के साथ सत्ता हासिल की। सत्ता में आने के बाद उसने एक हद तक लोकरंजक व 'कल्याणकारी राज्य' के कुछ कदमों को लागू किया। इससे निजी पूंजीपति वर्ग का एक हिस्सा, बड़े फार्मरों का एक हिस्सा उसके विरुद्ध हो गया। लेकिन राज्य के मालिकाने में पी.डी.वी.एस.ए. जैसी तेल कम्पनी से होने वाली राजस्व आय पर मुनाफा कमाने वाला नौकरशाह पूंजीपति वर्ग ह्यूगो चावेज के पक्ष में है। यह नौकरशाह पूंजीपति वर्ग भी राष्ट्रीय सुधारवादी बुर्जुआ वर्ग का हिस्सा है। इसमें निजी पूंजीपति वर्ग तात्कालिक तौर पर ह्यूगो चावेज का विरोधी है। अमरीकी साम्राज्यवाद का भी विरोध तात्कालिक है। इस विरोध का कारण लातिन अमरीका में अमरीकी वर्चस्व को मिलने वाली चुनौती है। लेकिन लम्बे दौर के लिए देखने पर यह साफ हो जायेगा कि ह्यूगो चावेज न तो वेनेजुएला के अंदर पूंजीवाद का विरोधी है और न ही अमरीकी साम्राज्यवाद का। वह अमरीकी साम्राज्यवादी वर्चस्व के विरुद्ध है। ह्यूगो चावेज उसी राष्ट्रीय सुधारवादी बुर्जुआ वर्ग की तरह आचरण करेगा, जैसा कि अन्य देशों के इस वर्ग के लोग करते हैं।

तब भी, यह सवाल बना रहता है कि ह्यूगो चावेज के अमरीकी साम्राज्यवाद विरोधी, नव उदारवाद-विरोधी उग्र तेवर के क्या कारण हैं? यह राष्ट्रीय सुधारवादी बुर्जुआ वर्ग की अपने लिए और ज्यादा जगह पाने तथा अपनी स्वाधीनता की चाहत की आम अभिव्यक्ति है। यह नवउदारवादी नीतियों व अमरीकी वर्चस्व के अंतर्गत वेनेजुएला की भयानक गरीबी और अभाव के बीच सम्पन्नता के कुछ द्वीपों के बीच बढ़ती खाई के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया है। तेल भंडार से मिलने वाले विपुल राजस्व की ताकत ने वह आर्थिक आधार दिया है, जिसके बल पर इस सरकार को अमरीकी साम्राज्यवाद विरोधी उग्र तेवर अपनाने में मदद मिलती है।।

अर्जेन्टाइना के राष्ट्रपति क्रिचनर व बोलीविया के इवो मोरालेस

अर्जेन्टाइना के राष्ट्रपति क्रिचनर ने 2003 के अंत में घरेलू बैंकपतियों के साथ एक बैठक में घोषणा की थी,"यदि हम राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग को मजबूत नहीं करते तो राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण असम्भव है।" इसके पहले वे "राष्ट्रीय पूंजीवाद" के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दे चुके थे।

क्रिचनर ने दिसम्बर 2001 में व्यापक जनउभार के बाद पूंजीवादी व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की है। वह चावेज की तरह घोर अमरीका विरोधी भी नहीं है और न ही उसे अपने यहां पूंजीपति वर्ग के किसी भी हिस्से के कट्टर विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

घरेलू नीतियों के मामले में क्रिचनर ने बन्द उद्योगों को बहाल करने तथा कृषि नीति को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों को वित्तीय सुविधा एवं सब्सिडी उपलब्ध करायी है। लेकिन कर्मचारियों और मजदूरों के वेतन अभी भी 1998 के स्तर को ही किसी तरह छू सके हैं। गरीबी का स्तर अभी भी 40% के आसपास है।

क्रिचनर की घरेलू व विदेश नीति में ऐसी कोई बात नहीं है जो उसको किसी भी तरह साम्राज्यवाद-विरोधी सिद्ध करती हो। 2001 में दिसम्बर के व्यापक जनउभार के कारण वह लोगों की भावनाओं को कुछ राहत देने के लिए कभी-कभी कुछ बोल देता है। उसके आर्थिक व वित्तीय मंत्रियों के अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और बैंकों से लम्बे समय से रिश्ते रहे हैं।

इसी प्रकार बोलीविया का इवो मोरालेस ऐसा 'वामपंथी' नेता है जिसको नव-उदारवादी एजेण्डा अपनाने में कोई गुरेज नहीं है। उसकी पृष्ठभूमि दोनों, ग्रामीण व उग्रपरिवर्तनवादी रही है। इवो मोरालेस मूलवासी कोका किसानों के नेता के साथ-साथ 'समाजवाद' के लिए आंदोलन (MAS) के नेता भी रहे हैं। उनके सत्ता में आने से पहले जब पेट्रोल और गैस का राष्ट्रीयकरण करने के संघर्ष में बहुत सारे मजदूर, बेरोजगार, शहरी मजदूर और मूलवासी इण्डियन मजदूर मारे गये थे, तब उस समय उनकी इस आंदोलन में कोई हिस्सेदारी नहीं थी। ये जन उभार इतने व्यापक थे कि इनके

कारण दो राष्ट्रपतियों को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने इस जन उभार में भागीदारी तो नहीं ही की बल्कि इसके विपरीत नव उदारवादी कारलोस मेसा को राष्ट्रपति बनाने में समर्थन दिया।

मोरालेस ने तेल और प्राकृतिक गैस भण्डार का राष्ट्रीयकरण किया है। लेकिन इसका उद्देश्य विदेशी कम्पनियों को बाहर करना नहीं है बल्कि बोलीवियाई राज्य के राजस्व को बढ़ाना है। इसीलिए उन्होंने सभी विदेशी कम्पनियों को 180 दिन का समय इस बात के लिए दिया है कि वे पुराने समझौते के स्थान पर नयी ऊंची राजस्व दरों के हिसाब से समझौते कर लें।

*　　　*　　　*

इन लातिन अमरीकी देशों में अमरीकी साम्राज्यवादियों के वर्चस्व के विरुद्ध किसी न किसी रूप में आवाज उठाने वाले लोग सत्तासीन हैं। ये अपने-अपने देशों के राष्ट्रीय सुधारवादी पूंजीपति वर्ग के प्रतिनिधि हैं। ये यभी आने-अपने देशों में निजी सम्पत्ति के समर्थक हैं। ये साम्राज्यवाद विरोधी नहीं हैं। इनका 'राष्ट्रवाद' साम्राज्यवादी देशों से अपने देश के पूंजीपति वर्ग के मुनाफे को बढ़ाने में सौदेबाजी का हथियार है।

1980 और 1990 के दशक की नव उदारवादी नीतियों का असर समूचे लातिन अमरीकी देशों मे जितने भयानक परिणाम लेकर आया, उसने मेहनतकश आबादी के बड़े हिस्से के जीवन को नरक बना दिया था और इसने जनता के असंतोष, गुस्से और बेचैनी को भड़का दिया था। राष्ट्रीय सुधारवादी पूंजीपति वर्ग की पुरानी स्थापित पर्टियां जन समुदाय के बीच बेनकाब हो चुकी थीं और उनका जनाधार कमजोर पड़ गया था। राष्ट्रीय सुधारवादी पूंजीपति वर्ग के खोये हुए जनाधार को पाने और उसको विस्तृत करने में ये नयी सरकारें शासक वर्ग की एक और सुरक्षा पंक्ति हैं।

चूंकि ये 'समाजवादी' सरकारें पूंजीपति वर्ग की सुरक्षा पंक्ति हैं, इसलिए इनकी सामाजिक सुधार परियोजनायें, चाहे कितनी ही नेकनीयती से चलायी जायें, इनका असफल होना या एक सीमा के बाद ठहराव का शिकार होना लाजिमी है। इसका कारण खुद मुनाफे की व्यवस्था में है। पूंजीवादी व्यवस्था अपने मूल तर्क के विपरीत नहीं जा सकती। पूंजीवादी उद्यमों का मूल उद्देश्य अपने मुनाफे को अधिकतम करना होता है इसलिए ये सरकारें इसी उद्देश्य की सेवा करेंगी।

■■■